>

Title : Need to provide land entitlement to the people belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and other Backward Classes besides giving adequate compensation to them for the land acquired from them by the Government.

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आजादी के लगभग 62 वर्षों के बाद भी देश के कोने-कोने में रहने वाले अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग जो जंगलों, पहाड़ों में रहते हैं तथा इस देश में 70-75 फीसदी किसान, जिनका भविष्य खेती पर निर्भर करता है, उन लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया है। जब भी केन्द्र सरकार या प्रदेश सरकारें चाहती हैं, तभी उनकी जमीनों को उन्हें बिना बताये अधिगृहित करने का काम करती हैं और कोड़ियों के दाम में उनके मुआवजे को उनके खाते में डालने का काम करती हैं। इसके साथ-साथ उन कोड़ियों में ली गयी जमीन को फिर पूंजीपतियों को लाभ पहुचाने के लिए मुफ्त में देने का काम किया जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वह आज देश में किसान, जो इस देश का भविष्य है, उन किसानों की उनकी जमीनों का मालिकाना हक देने का काम करे। मैं यह भी मांग करना चाहता हूं कि यदि सरकार को जमीन अधिगृहित करना आवश्यक है, तो उनका बाजारी मूल्य देने का काम करे। धन्यवाद।